भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2004**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर राजसहायता

2004. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कुल उर्वरक आवंटन पर कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;
(ख) उर्वरक संयंत्रों के उन्नयन के लिए सरकार की क्या योजना है; और
(ग) जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई) 1,68,054 करोड़ रुपये है।

(ख): उर्वरक संयंत्रों के उन्नयन की कोई योजना नहीं है। पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं और कंपनियां अपने व्यवसाय संबंधी उतार-चढ़ाव (बिजनेस डायनामिक्स) के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त अनुरोधों की जांच के आधार पर, उर्वरक कंपनियों को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने एवं उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से एनबीएस के अंतर्गत नई पीएण्डके कंपनियों और उनके उर्वरक उत्पादों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नई निवेश नीति (एनआईपी) के तहत, यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक 12.7 लाख मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता वाली 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित

करने हेतु एक विशेष नीति का भी अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से आगे बढ़ाकर अधिकतम करने के उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। इन प्रयासों ने मिलकर यूरिया उत्पादन को 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़ाकर 2023-24 के दौरान 314.09 एलएमटी के रिकॉर्ड यूरिया उत्पादन में मदद की है।

(ग): सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और जल प्रतिधारण के लिए देश में ऑर्गैनिक खेती को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई के तहत, विभिन्न घटकों को कवर करने के लिए आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से आन-फार्म/आफ-फार्म आर्गेनिक आदानों के अधिकतर जैव उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, ऑर्गैनिक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि हेतु 3 वर्ष के लिए 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 32500/- रुपये प्रति हेक्टेयर के दर की सहायता स्कीम के तहत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म ऑर्गैनिक आदानों के लिए 3 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

सरकार ने गोबरधन पहल, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीमें/कार्यक्रम जैसे कि एमओपीएनजी की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) स्कीम, एमएनआरई का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, डीडीडब्ल्यूएस का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), आदि शामिल है, के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात, संयंत्रों में उत्पादित एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम को बढ़ावा देने के लिए 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है

प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 25 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी मंत्रिमंडल बैठक में 2481 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ एक स्टैंडअलोन केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) को मंजूरी दी है। मिशन का लक्ष्य देश भर में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती शुरू करना है।

****